

दवियांग कैदियों को बुनियादी जेल सुविधाएँ न देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है: सर्वोच्च न्यायालय

प्रलिस के लयः

[सर्वोच्च न्यायालय, दवियांगजनों के अधिकार अधनियम, 2016 \(RPwD अधनियम\), दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, हीमोफीलया, सकिल सेल एनीमया](#) ।

मेन्स के लयः

दवियांगजन अधिकार अधनियम, 2016 की मुख्य वशिषताएँ, जेलों में दवियांगजनों के लयि समावेशता और समान अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेश ।

[स्रोत: हनिदुस्तान टाइम्स](#)

चर्चा में क्यों?

Tभारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) (SC) ने एल मुगनाथम बनाम तमलिनाडु राज्य मामले (2025) में फैसला सुनाया की दवियांग कैदियों को जेलों में आवश्यक सुविधाओं से वंचति करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है ।

- इसमें जेलों में दवियांग कैदियों की गरमा और देखभाल सुनश्चिति करने के लयि [वकिलांग वयक्तयिों के अधिकार अधनियम, 2016 \(RPwD अधनियम\)](#) के अनुरूप सुधारों पर भी बल दिया गया ।

संरचनात्मक बाधाएँ दवियांग कैदियों के हाशयिकरण को कैसे बढ़ाती हैं?

- **संस्थागत दुरगमता:** अधकिांश जेल सुविधाएँ गतशीलता, संवेदी या संज्ञानात्मक दवियांग वाले वयक्तयिों के लयि संरचनात्मक रूप से दुरगम हैं ।
 - प्रशक्षति देखभालकर्त्ताओं की अनुपस्थति और उपयुक्त अभरिक्षा नीतयिों के अभाव के कारण दवियांग कैदयिों को दैनकि देखभाल — जैसे नहाने, खाना खाने और कपडे पहनने में सहायता — से वंचति होना पड़ता है, जसिसे उनकी परेशानयिों और अधकि बढ़ जाती है ।
 - न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कइस तरह की दुरगमता कैदयिों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, जसिमें भारतीय संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनकी गरमा भी शामिल है ।
- नौकरशाही की उदासीनता और संस्थागत संवेदनशीलता की कमी के कारण स्वतंत्र समाज में सामाजकि बहष्कार का सामना करना पड़ता है, जो हरिसत में और भी तीव्र हो जाता है ।
- **प्रक्रयागत भेदभाव:** दुभाषयिों, सांकेतिक भाषा सुविधा प्रदाताओं और परीक्षण कार्यवाही में सुलभ प्रारूपों की कमी के कारण नष्पिक्ष सुनवाई में बाधा उत्पन्न होती है ।
 - सहायक प्रौद्योगकियिों, देखभालकर्त्ताओं या संचार साधनों की अनुपस्थति को "अप्रत्यक्ष भेदभाव" माना गया ।
 - चकितिसीय आवश्यकताओं की उपेक्षा: जेलों में समर्पति फजियिथेरेपी, मनोचकितिसा या मनोरोग देखभाल सुविधाओं की अनुपस्थति से स्वास्थय में अनावश्यक गरिवट आती है ।
- **आँकड़ों में कमी:** NCRB कैदयिों की वकिलांगता की स्थतिदरज नहीं करता, जसिसे नीतनिरमाण और लक्षति हस्तक्षेप में बाधा उत्पन्न होती है ।
- **दवियांगजन अधिकार अधनियम, 2016 का उल्लंघन:** सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय में दवियांगजन अधिकार अधनियम, 2016 कीधारा 6, 25 और 38 के उल्लंघनों पर प्रकाश डाला गया है, जो जेलों सहति संस्थानों में सुलभ बुनियादी ढाँचे और उचति आवास की वयवस्था को अनवार्य बनाते हैं ।
 - न्यायालय ने जेल मैनुअल की आलोचना करते हुए कहा कयिह पुराना है तथा RPwD अधनियम, 2016 या पूर्व न्यायकि नरिणयों के अनुरूप नहीं है ।

हरिसत में दवियांगजनों के संवैधानिक और कानूनी अधिकार क्या हैं?

- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** जब आधारभूत देखभाल से इनकार किया जाता है तो अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का सीधे तौर पर उल्लंघन होता है।
 - न्यायालय ने पुष्टि की कि कारावास सम्मान, मानवीय व्यवहार या आवश्यक सुविधाओं से वंचित करने का औचित्य नहीं देता है।
- **RPwD अधिनियम, 2016 के प्रावधान:**
 - धारा 6: जोखिम की स्थितियों में सुरक्षा और संरक्षा, जिसमें हरिसत की स्थितियाँ भी शामिल हैं।
 - धारा 25: नविकार और पुनर्वास सेवाओं सहित स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच।
 - धारा 38: कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणालियों सहित सभी सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर का आदेश।
- **अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ:** वकिलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) का अनुच्छेद 15, जिस पर भारत भी हस्ताक्षरकर्ता है, हरिसत में वकिलांग व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार के क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार को प्रतिबंधित करता है।

दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

- **परिचय:** यह अधिनियम दवियांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCRPD) को प्रभावी बनाने के लिये भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसने भारत द्वारा वर्ष 2007 में अनुमोदित किया था।
 - यह अधिनियम पहले के न:शिक्षित व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान लेता है, जिसने भारत में दवियांगजनों की ज़रूरतों और चुनौतियों को संबोधित करने में अपर्याप्त तथा पुराना माना जाता था।
 - जनगणना 2011 के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दवियांग व्यक्तियाँ हैं, जो कुल जनसंख्या का 2.21% हैं।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
 - दवियांगता की वसितारित परिभाषा: दवियांगता के प्रकारों को मौजूदा 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है, जिसमें पहली बार एसडि अटैक पीड़ितों, **हीमोफीलिया और सकिल सेल एनीमिया** जैसी रक्त संबंधी बीमारियों को भी शामिल किया गया है।
 - अधिकार एवं पात्रता: वकिलांग व्यक्तियों के समान अधिकार सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी संबंधित सरकारों की है।
 - यह मानक वकिलांगता वाले व्यक्तियों और उच्च सहायता की आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करता है, जिसमें उच्च शिक्षा में न्यूनतम 5% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में 4% और भूमि आवंटन में 5% आरक्षण शामिल है।
 - सार्वजनिक भवनों के लिये अधिदेश: दवियांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत केंद्र सरकार को सार्वजनिक भवनों, परिवहन और आईसीटी अवसंरचना में दवियांगजनों के लिये सुगम्यता मानक निर्धारित करने की आवश्यकता है।

दवियांगजन के अनुकूल जेल बनाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य नरिदेश क्या हैं?

- **दवियांग कैदियों की पहचान:** जेल अधिकारियों को कैदियों के प्रवेश के समय ही उनकी दवियांगता की पहचान करनी होगी, जिससे वे अपनी स्थिति और विशेष आवश्यकताओं की जानकारी दे सकें।
- **सार्वभौमिक पहुँच:** जेल के नियमों और आवश्यक जानकारी को ब्रेल, बड़े अक्षरों में प्रिंट, संकेत भाषा (साइन लैंग्वेज) या सरल भाषा जैसे सुलभ प्रारूपों में प्रदान किया जाना चाहिये ताकि सभी कैदियों के लिये जानकारी सुलभ हो सके।
 - जेल परिसरों में व्हीलचेयर-अनुकूल स्थान, सुलभ शौचालय और रैंप होने चाहिये ताकि दवियांग कैदियों को स्वतंत्र रूप से आने-जाने में कोई कठिनाई न हो।
- **चिकित्सीय सुविधाएँ:** सभी जेलों में फजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी और अन्य आवश्यक उपचारात्मक सेवाओं के लिये समर्पित स्थान होने चाहिये।
- **एक्सेस ऑडिट:** तमलिनाडु की सभी जेलों का राज्य-स्तरीय एक्सेस ऑडिट छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिये। यह कार्य एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें सामाजिक कल्याण विभाग, दवियांगजन कल्याण विभाग और प्रमाणित एक्सेस ऑडिटर्स के अधिकारी शामिल होंगे।
- **जेल अधिकारियों का प्रशिक्षण और संवेदनशीलता:** जेल कर्मचारियों को दवियांग कैदियों की आवश्यकताओं के संबंध में प्रशिक्षण और संवेदनशीलता प्रदान की जानी चाहिये, ताकि एक सहानुभूतिपूर्ण व जागरूक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जा सके।

नषिकर्ष

एल. मुगुनंथम बनाम तमलिनाडु राज्य मामले (2025) में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय समावेशी जेल सुधार की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दवियांगजन अधिकार अधिनियम को लागू करके और संवैधानिक व अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, यह नरिणय दवियांग कैदियों के लक्ष्यमान, सुगम्यता और मानवीय व्यवहार को सुदृढ़ करता है तथा उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत की जेल प्रणाली में दवियांग व्यक्तियों के सामने आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। कौन से सुधार आवश्यक हैं?

????????

प्रश्न. भारत लाखों दवियांग वयक्तियों का घर है। कानून के अंतरगत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उमर तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लयि भूमिका अधमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न: क्या नःशिक्षित वयक्तियों के अधिकार अधनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन की प्रभावी क्रयिावधिको सुनश्चिति करता है? चर्चा कीजयि। (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/denial-of-basic-prison-care-to-disabled-violates-fundamental-rights-sc>

